

Daily Current Affairs

Date : 01 June, 2026



अनुक्रमणिका

क्र. सं.	टॉपिक का नाम
1.	राजस्थान में 'डी-रेग्यूलेशन फेज - 1' की मासिक प्रगति रिपोर्ट
2.	'विकसित भारत वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम' में राजस्थान के 15 युवाओं का चयन
3.	ToFEI पुरस्कार प्राप्त करने वाला राजस्थान का एकमात्र राजकीय विद्यालय : राहोली
4.	ई-वेस्ट से 'सर्कुलर इकोनॉमी' की ओर बढ़ता राजस्थान
5.	'नगर वन योजना' के तहत बीजक की पहाड़ी का विकास
6.	न्यूज़ इन शॉर्ट्स 1. पुण्यश्लोक अहल्याबाई होल्कर की 301वीं जयंती (राज्य स्तरीय समारोह) 2. वैभव सूर्यवंशी (राजस्थान रॉयल्स) 3. थार ड्राई पोर्ट : हिरनोदा (जयपुर) 4. राजस्थान नगर पालिका कर्मचारी फेडरेशन का 9वाँ महाधिवेशन
7.	राष्ट्रीय बीज भंडार (NSR)
8.	स्काईकास्ट सिस्टम
9.	नई डिजिटल समुद्री पहलें
10.	कनाडा (राजधानी: ओटावा)
11.	भारत के सेमीकंडक्टर उद्योग का भविष्य" शीर्षक से रोडमैप
12.	राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS)-6
13.	बेबेसिया संक्रमण

-:1:-



राजस्थान परिदृश्य



राजस्थान में 'डी-रेग्यूलेशन फेज - 1' की मासिक प्रगति रिपोर्ट



चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, राजस्थान के मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा राज्य में 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को बढ़ावा देने के लिए 'डी-रेग्यूलेशन फेज-1' की मासिक प्रगति रिपोर्ट (अप्रैल माह के लिए) जारी की गई।



मुख्य बिन्दु:

- इस रिपोर्ट के अनुसार, राज निवेश पोर्टल पर प्राप्त 9,010 आवेदनों में से 6,103 आवेदनों (67.7 प्रतिशत स्वीकृति दर) को त्वरित मंजूरी दी गई है, जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है तथा प्रदेश को पसंदीदा निवेश गंतव्य बनाने और प्रक्रियाओं के सरलीकरण के लिए महत्वपूर्ण कदम है।
- ज्ञातव्य है कि मुख्य सचिव कार्यालय के अंतर्गत गठित 'डिरेगुलेशन सेल' द्वारा तैयार प्रदेश में निवेश प्रस्तावों के संदर्भ में मासिक प्रगति रिपोर्ट तैयार की जाती है।
- **राज निवेश पोर्टल** : विभिन्न निवेश आवेदनों को 'राज निवेश पोर्टल' के माध्यम से ऑनलाइन और त्वरित मंजूरी दी जाती है।
- **सर्वाधिक स्वीकृति प्रदान करने वाला ज़िला** : जयपुर (1932 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 1351 आवेदन स्वीकृत किए गए।)
- इसके अलावा कोटा और हनुमानगढ़ ने उच्च निस्तारण दक्षता प्रदर्शित करते हुए क्रमशः लगभग 83.8 प्रतिशत और 82.5 प्रतिशत की स्वीकृति दर की उपलब्धि हासिल की।

Daily Current Affairs



Date : 01 June, 2026



प्रमुख क्षेत्र :

- रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल माह में प्रदेश में आयुष, एगो-प्रोसेसिंग, रक्षा और शिक्षा जैसे उभरते क्षेत्रों में विभिन्न जिलों से आवेदन प्राप्त हुए हैं, जो राजस्थान में क्षेत्रीय विविधीकरण तथा निवेश अवसरों के विस्तार को दर्शाते हैं।

सेक्टरवाइज प्रगति :

- **पर्यटन एवं आतिथ्य क्षेत्र** : इस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रस्तावित निवेश दर्ज किया गया, जिसमें जयपुर, उदयपुर, पाली, राजसमंद और सीकर का प्रमुख योगदान रहा।
- **इंजीनियरिंग** : अलवर एवं कोटपूतली-बहरोड़ का प्रमुख स्थान रहा।
- **वेस्ट मैनेजमेंट** : अजमेर एवं भीलवाड़ा।
- **टैक्सटाइल क्षेत्र** : जोधपुर।

UTKARSH

CIVIL
SERVICES

--3--



उत्कर्ष® Jodhpur : JALORI GATE CIRCLE, JODHPUR | Support@utkarsh.com | Call us at : 9829 213 213
Jaipur : NEAR MAHESH NAGAR THANA, GOPALPURA BYPASS ROAD, JAIPUR

‘विकसित भारत वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम’ में राजस्थान के 15 युवाओं का चयन

चर्चा में क्यों?

- केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी 'विकसित भारत वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम' में भाग लेने के लिए राजस्थान के 15 'माय भारत' (MY Bharat) स्वयंसेवकों का चयन किया गया है।



मुख्य बिन्दु:

- देशभर से चयनित 100 युवाओं के दल में राजस्थान के 15 स्वयंसेवक हिमाचल प्रदेश के सीमावर्ती गाँवों में राष्ट्र निर्माण एवं जनजागरूकता गतिविधियों में भाग लेंगे।
- 'विकसित भारत वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम' का संचालन : केन्द्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय तथा केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से।
- उद्देश्य : युवाओं को सीमावर्ती गाँवों में भेजकर देश की विविधता और चुनौतियों से रूबरू कराना।
- इस कार्यक्रम के लिए युवाओं का चयन राष्ट्रीय प्रतियोगिता के माध्यम से किया गया है, जिसके तहत युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के अंतर्गत 'माय भारत पोर्टल' पर 'विकसित भारत वाइब्रेंट विलेज क्विज' का आयोजन किया गया था।
- इस राष्ट्रव्यापी क्विज में देश भर से कुल 2.59 लाख युवाओं ने हिस्सा लिया, जिसमें राजस्थान के 16 हजार से अधिक युवाओं ने भाग लिया।

ToFEI पुरस्कार प्राप्त करने वाला राजस्थान का एकमात्र राजकीय विद्यालय : राहोली

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, पीएमश्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, राहोली (टोंक) को 'टोबैको फ्री एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चैलेंज अवॉर्ड' (ToFEI) प्रदान किया गया। ToFEI पुरस्कार प्राप्त करने वाला यह राजस्थान का एकमात्र राजकीय विद्यालय है।



मुख्य बिन्दु:

- ToFEI अवॉर्ड केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय के तहत स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा प्रदान किए जाने वाला एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार है।
- मुख्य उद्देश्य :** स्कूलों को तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान (Tobacco-Free Educational Institutions) के दिशा-निर्देशों का पालन करने और छात्रों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने के लिए प्रेरित करना।

- स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (DoSEL) द्वारा तीन-वर्षीय 'नशा मुक्त विद्यालय कार्य योजना' (2026-2029) का संचालन किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य तंबाकू की रोकथाम, जागरूकता, निगरानी और क्षमता-निर्माण की पहलों को मज़बूत करना है।
- **नोट :** हाल ही में, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा वर्ष 2026 के 'वर्ल्ड नो टोबैको डे अवॉर्ड' के तहत राजस्थान को विश्व स्तरीय सम्मान प्रदान किया गया।

अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु :

तंबाकू के उपभोग को नियंत्रित करने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा किए गए प्रयास :

- **राज्यव्यापी विशेष प्रवर्तन एवं जन-जागरूकता अभियान :** चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा 22 से 30 मई, 2026 तक सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 (COTPA) के अंतर्गत राज्यव्यापी विशेष प्रवर्तन एवं जन-जागरूकता अभियान का संचालन किया गया।
- **तम्बाकू मुक्ति उपचार एवं परामर्श केन्द्र :** राज्य भर में ब्लॉक स्तर तक 500 से अधिक तम्बाकू मुक्ति उपचार एवं परामर्श केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है। इन केंद्रों को जियो-टैग कर आमजन की सुविधा के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया गया है ताकि जरूरतमंद व्यक्ति निकटतम केंद्र तक आसानी से पहुंच सके।
- साथ ही, तम्बाकू लत छुड़ाने के उपचार के लिए निकोटिन रिप्लेसमेन्ट थेरेपी को आवश्यक दवा सूची में सम्मिलित किया गया है।
- **'देवदारवादि धूम्र' :** राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान (NIA), जयपुर द्वारा विकसित एक हर्बल और आयुर्वेदिक सिगरेट है, जिसे मुख्य रूप से लोगों को निकोटिन और तंबाकू की लत से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।

फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स:

- **विश्व तंबाकू निषेध दिवस :** विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रति वर्ष 31 मई को।
- **वर्ष 2026 की विषयवस्तु :** "आकर्षण का नकाब हटाना - निकोटीन और तंबाकू की लत का मुकाबला।" (Unmasking the appeal - countering nicotine and tobacco addiction)

ई-वेस्ट से 'सर्कुलर इकोनॉमी' की ओर बढ़ता राजस्थान



चर्चा में क्यों?

- राजस्थान ई-वेस्ट (इलेक्ट्रॉनिक कचरा) प्रबंधन के जरिए 'सर्कुलर इकोनॉमी' (चक्रीय अर्थव्यवस्था) को अपनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

ई-वेस्ट से 'सर्कुलर इकोनॉमी' की ओर बढ़ता राजस्थान

आज का ई-वेस्ट, कल का संसाधन | स्वच्छ पर्यावरण, समृद्ध राजस्थान

ई-वेस्ट नहीं, संसाधन है, समाधान है, भविष्य है!

1 'रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल' (3R)

REDUCE रिड्यूस कम उपयोग, कम ई-वेस्ट
REUSE रीयूज पुनः उपयोग, जीवन बढ़ाएँ
RECYCLE रिसाइकल वैज्ञानिक तरीके से पुनर्चक्रण

कम कचरा • अधिक संसाधन • बेहतर भविष्य

2 'वेस्ट-टू-वेल्थ' और स्टार्टअप्स को बढ़ावा

ई-वेस्ट → वैल्यू / संपदा

नवाचार और लोभ • युवा उद्यमिता को बढ़ावा • स्थानीय उद्योग और रोजगार • आर्थिक वृद्धि और समृद्धि

कचरे से कमाई, विचार से बदलाव!

3 ई-कचरा पुनर्चक्रण पार्क

आधुनिक अवसंरचना, सुरक्षित और वैज्ञानिक प्रबंधन

1. संग्रह एवं छंटाई • ई-वेस्ट का सुरक्षित संग्रह और वर्गीकरण
2. डीसेम्बलिंग • कुशलतापूर्वक अलग करना
3. रिकवरी • पुनः उपयोग, रिसाइकल या सुरक्षित

स्वच्छ तकनीक • सुरक्षित प्रक्रिया • हरित कर्जा • शून्य प्रदूषण

ई-वेस्ट से क्या-क्या प्राप्त होता है?

सोना (Au) • चांदी (Ag) • तांबा (Cu) • एल्युमिनियम (Al) • प्लास्टिक • कांच • दुर्लभ धातुएँ

आओ मिलकर बनाएं स्वच्छ, हरित और आत्मनिर्भर राजस्थान



मुख्य बिन्दु:

- राज्य सरकार लीनियर इकोनॉमी के मॉडल को बदलकर 'रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल' (3R) के सिद्धांत को अपना रही है।
- **ई-वेस्ट** : ई-वेस्ट (E-Waste) या इलेक्ट्रॉनिक कचरा उन सभी खराब, पुराने या अनुपयोगी बिजली और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को कहा जाता है, जिन्हें उनके उपयोगकर्ताओं द्वारा फेंक दिया जाता है। जब कोई मोबाइल, कंप्यूटर या घरेलू उपकरण काम करना बंद कर देता है या उसकी जीवन अवधि समाप्त हो जाती है, तो वह ई-वेस्ट बन जाता है।

राजस्थान सरकार द्वारा किए गए प्रमुख प्रयास :

- **राजस्थान ई-वेस्ट प्रबंधन नीति - 2023** : राजस्थान सरकार द्वारा 5 जून, 2023 (विश्व पर्यावरण दिवस) को 'राजस्थान ई-वेस्ट प्रबंधन नीति - 2023' की घोषणा की गई।
- **राजस्थान सर्कुलर इकोनॉमी इंसेंटिव स्कीम (RCEIS)** : अपशिष्ट प्रबंधन, रीसाइक्लिंग और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई एक प्रमुख पहल।
- **इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क** : जयपुर के जमवारामगढ़ (थौलाई गाँव) में एक अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क स्थापित किया गया है।
- **ई-वेस्ट संग्रहण वाहन** : 5 जून, 2025 को को मुख्यमंत्री ने सात संभागीय मुख्यालयों और औद्योगिक शहरों में ई-वेस्ट संग्रहण के लिए 11 ई-वेस्ट संग्रहण वाहनों को रवाना किया।

अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु:

राजस्थान ई-वेस्ट प्रबंधन नीति - 2023:

- **घोषणा** : विश्व पर्यावरण दिवस - 2023 के अवसर पर।
- **नीति का मुख्य उद्देश्य** : राज्य में बढ़ते ई-वेस्ट की चुनौतियों से निपटना और इसके प्रबंधन के लिए एक मजबूत ढाँचा तैयार करना।
- **नोडल एजेंसी** : राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल (RSPCB)

मुख्य उद्देश्य और विजन

- **वैज्ञानिक निस्तारण** : ई-वेस्ट के वैज्ञानिक और पर्यावरणीय रूप से सुरक्षित प्रबंधन को बढ़ावा देना।
- **चक्रीय अर्थव्यवस्था (Circular Economy)** : 'रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल' (3Rs) के सिद्धांत पर काम करते हुए राज्य को सर्कुलर इकोनॉमी की ओर ले जाना।
- **प्रदूषण नियंत्रण** : इलेक्ट्रॉनिक कचरे के अनुचित निपटान से होने वाले वायु, जल और मृदा प्रदूषण को रोकना।

फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स:

- **भारत की स्थिति** : भारत दुनिया में चीन और अमेरिका के बाद तीसरा सबसे बड़ा ई-वेस्ट पैदा करने वाला देश है।
- वर्ष 2024 में राज्यसभा में प्रस्तुत आँकड़ों के अनुसार, भारत में पिछले पाँच वर्षों में ई-वेस्ट के उत्पादन में भारी वृद्धि देखी गई है, जो 2019-20 में 1.01 मिलियन मीट्रिक टन (MMT) से बढ़कर 2023-24 में 1.751 MMT हो गया है।
- भारत में ई-वेस्ट के बढ़ते दबाव को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा ई-वेस्ट (प्रबंधन) नियम, 2022 और 2024 लाए गए हैं।
- इसके तहत विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR), ई-वेस्ट के वैज्ञानिक पुनः उपयोग, रीसाइकल और रीफर्बिशिंग के महत्त्व, सकुलर इकोनॉमी की दिशा में कदम बढ़ाने आदि जैसे विषयों पर जोर दिया गया है, ताकि उद्योगों द्वारा ई-वेस्ट से उत्पन्न पर्यावरणीय दुष्प्रभावों को नियंत्रित किया जा सके।

‘नगर वन योजना’ के तहत बीजक की पहाड़ी का विकास

चर्चा में क्यों?

- कोटपूतली-बहरोड़ के विराटनगर क्षेत्र में स्थित ऐतिहासिक बीजक की पहाड़ी को राजस्थान वन विभाग द्वारा केन्द्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) की ‘नगर वन योजना’ के तहत विकसित किया जा रहा है।



मुख्य बिन्दु:

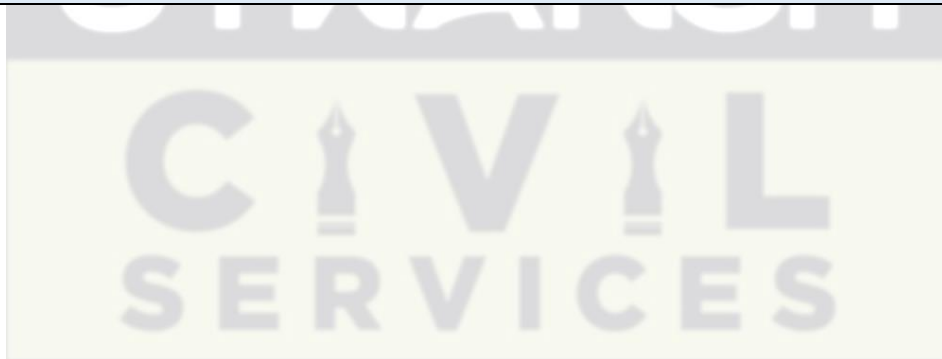
- यह प्रोजेक्ट अरावली क्षेत्र में प्राकृतिक संतुलन को मजबूत करने और इको-टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।
- उद्देश्य :** जैव विविधता का संवर्धन, पर्यावरण संरक्षण और क्षेत्र में हरित विकास को नई दिशा देना।

- इसी योजना के अंतर्गत झालावाड़ के प्रसिद्ध वन क्षेत्र ठंडी झिरी (मंगलनाथ की डूंगरी) और प्रमुख शहरों; जैसे - उदयपुर, कोटा, अजमेर व जयपुर में भी नगर वनों का विकास किया जा रहा है।
- **लक्ष्य :** राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनरोपण प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (CAMPA) के राष्ट्रीय कोष की वित्तीय सहायता से वर्ष 2027 तक 1000 नगर वन विकसित करना।
- **वित्तीय सहयोग :** पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) इस योजना के तहत शहरी वनों के निर्माण और रखरखाव के लिए प्रति हेक्टेयर ₹4 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
- **क्षेत्रफल :** नगर वन क्षेत्र न्यूनतम 10 हेक्टेयर से लेकर 50 हेक्टेयर तक हो सकता है। इस योजना में नगर निगमों, नगर पालिकाओं और शहरी स्थानीय निकायों (ULB) वाले सभी शहर शामिल हैं।
- प्रत्येक नगर वन में कम से कम दो-तिहाई क्षेत्र वृक्षों से आच्छादित होना चाहिए और इसमें जैव विविधता पार्क, स्मृति वन, तितली संरक्षण केंद्र और हर्बल गार्डन जैसे घटक शामिल होंगे।
- इस पहल से शहरों के भीतर और आसपास की वन भूमि को क्षरण और अतिक्रमण से बचाने में मदद मिलेगी और वायु प्रदूषण, शहरी ताप द्वीप, जैव विविधता का नुकसान, आवास का क्षरण आदि जैसी पर्यावरणीय समस्याओं का भी समाधान होगा।

✂ न्यूज़ इन शॉर्ट्स ⚡

क्र. सं.	न्यूज़
1.	पुण्यश्लोक अहल्याबाई होल्कर की 301वीं जयंती (राज्य स्तरीय समारोह) - पुण्यश्लोक लोकमाता अहल्याबाई होल्कर की 301वीं जयंती के अवसर पर 31 मई, 2026 को जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। - कार्यक्रम में अहल्याबाई होल्कर के जीवन पर आधारित पुस्तक का विमोचन किया गया। - लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर (1725 - 1795) मराठा साम्राज्य के होल्कर राजवंश की एक महान और दूरदर्शी शासिका थीं।
2.	वैभव सूर्यवंशी (राजस्थान रॉयल्स) - IPL - 2026 में राजस्थान रॉयल्स (RR) के बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने ऑरेंज कैप अपने नाम की। - वह IPL इतिहास में ऑरेंज कैप जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी हैं। वैभव ने इस सीजन खेले 16 मैचों में 48.50 की औसत और 237.31 के स्ट्राइक रेट से कुल 776 रन बनाए। कुल 5 अवॉर्ड्स: - ऑरेंज कैप (सबसे ज्यादा रन - 776) - मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर (436.3 अंक) - इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन। - सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन (237.31 की स्ट्राइक रेट) - मोस्ट सिक्ससेस इन टूर्नामेंट (सबसे ज्यादा छक्के - 72)

3.	थार ड्राई पोर्ट : हिरनोदा (जयपुर) ■ हाल ही में, 'राइजिंग राजस्थान इनिशिएटिव' और 'प्रधानमंत्री गति शक्ति मास्टर प्लान' के अंतर्गत जयपुर जिले के हिरनोदा में नए थार ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया गया। ■ अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त यह मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स हब क्षेत्रीय संपर्क, विनिर्माण और आयात-निर्यात गतिविधियों को बढ़ावा देगा। ■ पोर्ट का संचालन : हस्ती पेट्रोकेमिकल्स एंड शिपिंग लिमिटेड (HPCSL) और ब्रुकमैन लॉजिस्टिक्स द्वारा संयुक्त रूप से।
4.	राजस्थान नगर पालिका कर्मचारी फेडरेशन का 9वाँ महाधिवेशन ■ राजस्थान नगर पालिका कर्मचारी फेडरेशन का 9वाँ महाधिवेशन 30 मई, 2026 को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर (RIC) जयपुर में संपन्न हुआ। ■ स्मारिका का विमोचन : कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा 'कर्मचारी कल्याण स्मारिका' का विमोचन किया गया।





राष्ट्रीय परिदृश्य



राष्ट्रीय बीज भंडार (NSR)

(स्रोत: NEWS ON AIR)



चर्चा में क्यों?

- केंद्रीय कृषि मंत्री ने 1 लाख 74 हजार क्विंटल के 'राष्ट्रीय बीज भंडार' की स्थापना करने की घोषणा की है।



मुख्य बिन्दु:

राष्ट्रीय बीज भंडार (NSR)

- यह 'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और पोषण मिशन' (NFSNM) के 'कृषोन्नति योजना' के तहत शुरू की गई एक पहल है।
- **उद्देश्य:** किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले प्रमाणित और आधार बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करना, विशेष रूप से संकट या प्राकृतिक आपदाओं के समय।
- **कार्यान्वयन एजेंसियाँ:** राष्ट्रीय बीज निगम, राज्य बीज निगम और राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्रों के कृषि विभाग (जहाँ राज्य बीज निगम मौजूद नहीं हैं)।
- राष्ट्रीय बीज भंडार में रखे जाने वाले बीजों का उत्पादन 'साथी/SATHI' (सीड ट्रेसेबिलिटी, ऑथेन्टिकेशन एंड होलिस्टिक इन्वेंट्री) पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा।

स्काईकास्ट सिस्टम

(स्रोत: PIB)



चर्चा में क्यों?

- हाल ही में स्वीकृत मिशन मौसम पहल के तहत भारत, इंदिरा गाँधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 'स्काईकास्ट सिस्टम' स्थापित करने वाला विश्व का 19वाँ देश बन गया है।



मुख्य बिन्दु:

स्काईकास्ट सिस्टम

- स्काईकास्ट एक अत्याधुनिक वायुमंडलीय निगरानी और मौसम पूर्वानुमान प्रणाली है, जिसे वास्तविक समय में मौसम संबंधी जानकारी प्रदान करके विमानन सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए विकसित किया गया है।
- यह रडार विंड प्रोफाइलर, SODAR, माइक्रोवेव रेडियोमीटर, ग्राउंड-बेस्ड फॉग एरोसोल स्पेक्ट्रोमीटर (GFAS), और CL61 लिडार-आधारित सीलोमीटर जैसी तकनीकों को एकीकृत करता है।
- स्काईकास्ट प्रणाली, विंटर फॉग एक्सपेरिमेंट (WiFEX) से प्राप्त अनुभवों और निष्कर्षों पर आधारित है।
- यह परियोजना 2015 में दिल्ली के इंदिरा गाँधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (IITM) और भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) द्वारा, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत शुरू की गई थी।

--:15:--

📦 योजनाएँ एवं नीतियाँ 📦

नई डिजिटल समुद्री पहलें

(स्रोत: PIB)



चर्चा में क्यों?

- केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने समुद्री क्षेत्र के लिए नई डिजिटल पहलों की शुरुआत की।



मुख्य बिन्दु:

- ये डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म पोत परिवहन के क्षेत्रक में सेवा-प्रदायगी, पारदर्शिता और जवाबदेही को बेहतर बनाएंगे।

नई डिजिटल समुद्री पहलें

- **यूनिफाइड शिप रीसाइक्लिंग क्रेडिट नोट मॉड्यूल:** नई 'जहाज पुनर्चक्रण क्रेडिट योजना' के तहत एक पोर्टल शुरू किया गया है। इसमें हांगकांग कन्वेंशन के अनुरूप भारतीय शिपयार्डों में जहाजों का पुनर्चक्रण कराने वाले जहाज मालिकों को जहाज के कबाड़ मूल्य का 40% के बराबर क्रेडिट नोट दिया जाएगा।
- यह योजना सरकार के ₹70,000 करोड़ के समुद्री क्षेत्र विकास पैकेज का हिस्सा है, जिसकी घोषणा 2025 में की गई थी।
- **महत्व:** यह प्लेटफॉर्म भारत में जहाज निर्माण और चक्रीय अर्थव्यवस्था (सर्कुलर इकोनॉमी) को बढ़ावा देगा।
- **जहाजों के सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल पद्धति से पुनर्चक्रण हेतु हांगकांग अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन:** अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) के तहत यह एक वैश्विक संधि है। यह जून 2025 से प्रभावी है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जहाजों का पुनर्चक्रण मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए खतरा उत्पन्न न करे।

Daily Current Affairs



Date : 01 June, 2026



- **e-नाविक (e-Navik):** यह 24x7 शिकायत निवारण पोर्टल है। इसके माध्यम से भारतीय नाविक व्हाट्सएप, हेल्पलाइन या ईमेल के जरिए कहीं से भी अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं।
- यह पहल समुद्री श्रम कन्वेंशन, 2006 के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
- **जहाजों के पंजीकरण के लिए e-समुद्र (e-Samudra) मॉड्यूल:** यह जहाज पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाकर भारतीय समुद्री क्षेत्र प्रशासन को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाता है।
- **मेडिकल प्रैक्टिशनर मॉड्यूल:** यह उन डॉक्टरों के पंजीकरण और निगरानी के लिए है जो नाविकों को स्वास्थ्य प्रमाण पत्र देते हैं। इसका लक्ष्य फर्जी प्रमाण पत्रों को रोकना है।

UTKARSH

CIVIL
SERVICES

-:17:-



उत्कर्ष®

Jodhpur : JALORI GATE CIRCLE, JODHPUR | Support@utkarsh.com | Call us at : 9829 213 213
Jaipur : NEAR MAHESH NAGAR THANA, GOPALPURA BYPASS ROAD, JAIPUR



अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य



कनाडा (राजधानी: ओटावा)

(स्रोत: PIB)



चर्चा में क्यों?

- कनाडा और भारत ने एक मंच के रूप में 'व्यापार एवं निवेश मंच' की शुरुआत की। यह एक ऐसा मंच है, जो कनाडा और भारत के व्यावसायिक नेताओं को एक साथ लाता है तथा नए व्यावसायिक साझेदारी अवसरों और व्यापारिक सहयोग को बढ़ावा देता है।



-:18:-



मुख्य बिन्दु:

भौगोलिक विशेषताएँ

- **आकार:** रूस के बाद यह विश्व का दूसरा सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला देश है।
- **भू-दृश्य:** इसमें आर्कटिक टुंड्रा, विशाल बोरियल वन, रॉकी पर्वतमाला और उपजाऊ घास के मैदान शामिल हैं।
- **स्वच्छ जल:** कनाडा की झीलों, नदियों एवं अन्य स्रोतों में विश्व का 20% स्वच्छ जल भंडार संग्रहित है।
- **महान झीलें (ग्रेट लक्स):** 5 महान झीलें (सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, ओंटारियो और एरी) कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती हैं।
- इन 5 झीलों में से, केवल मिशिगन झील ही पूरी तरह से अमेरिका की सीमा के भीतर स्थित है।

UTKARSH

CIVIL
SERVICES

⌚ विज्ञान प्रौद्योगिकी ⚡

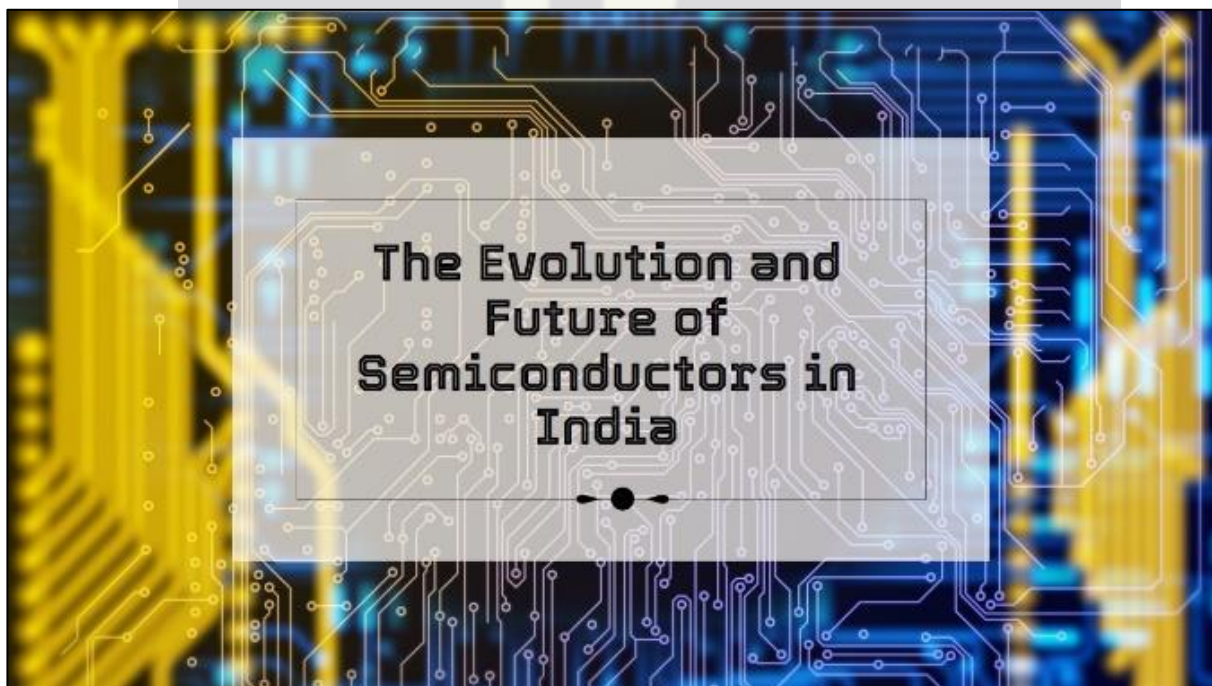
भारत के सेमीकंडक्टर उद्योग का भविष्य" शीर्षक से रोडमैप

(स्रोत: PIB)



चर्चा में क्यों?

- नीति आयोग ने "भारत के सेमीकंडक्टर उद्योग का भविष्य" शीर्षक से रोडमैप जारी किया।



मुख्य बिन्दु:

रोडमैप के मुख्य लक्ष्य

- वर्ष 2035 तक 120-150 बिलियन डॉलर की एक मजबूत सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला बनाना।
- वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार में 10-13% हिस्सेदारी प्राप्त करना तथा अत्याधुनिक पैकेजिंग और आउटसोर्सड सेमीकंडक्टर असेंबली एवं टेस्टिंग के क्षेत्र में विश्व के शीर्ष 3 प्रमुख केंद्रों में शामिल होना।

- वर्ष 2030 तक सेमीकंडक्टर चिप विनिर्माण में 15-25% आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, जिसे 2035 तक बढ़ाकर 35-50% करना।
- वर्ष 2035 तक देश में उपयोग होने वाली प्रत्येक चिप के वैल्यू चेन का 55-70% घटक देश में ही उपलब्ध कराना।

रोडमैप: 5 मुख्य स्तंभ

- **अग्रणी बनना (अनुसंधान एवं विकास तथा डिज़ाइन आईपी):** अत्याधुनिक अनुसंधान और चिप डिज़ाइन में स्वदेशी क्षमताओं का विकास करना, ताकि 2035 तक 100 से अधिक उन्नत सेमीकंडक्टर बौद्धिक संपदा विकसित की जा सकें।
- **नीति और निवेश:** सेमीकंडक्टर उद्योग के विकास के लिए 135-180 बिलियन डॉलर का निवेश जुटाना।
- पूर्ण प्रोत्साहन व्यवस्था के साथ एक स्वायत्त 'राष्ट्रीय सेमीकंडक्टर नोडल एजेंसी' की स्थापना करना, जो दीर्घकालिक और स्पष्ट नीतिगत दिशा प्रदान करे तथा सेमीकंडक्टर चिप की माँग को बढ़ावा दे।
- **उत्पादन :** रणनीतिक रूप से उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना जहाँ देश को स्वाभाविक बढ़त प्राप्त है (जैसे रक्षा और एयरोस्पेस), विशेष रूप से अत्याधुनिक पैकेजिंग, परिपक्व एवं कंपाउंड वेफर निर्माण (28-65 नैनोमीटर) पर जोर देना।
- **मानव संसाधन:** एक व्यापक 'राष्ट्रीय सेमीकंडक्टर प्रतिभा पिरामिड' विकसित करना, जिसके माध्यम से फैब-रेडी क्लीनरूम तकनीशियनों से लेकर एडवांस्ड सिस्टम-स्तरीय समाधान विशेषज्ञों तक सभी स्तरों के कार्यबल को प्रशिक्षित किया जा सके।
- **साझेदारी:** क्रिटिकल मिनरल्स की आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करने, वैश्विक अनुसंधान एवं विकास नेटवर्क से जुड़ने और प्रौद्योगिकी प्राप्ति में तेजी लाने के लिए अमेरिका, जापान और यूरोपीय संघ जैसे विश्वसनीय मित्रों तथा वैश्विक उद्योग जगत के साथ परिणाम-केंद्रित साझेदारियाँ स्थापित करना।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS)-6

(स्रोत: PIB)



चर्चा में क्यों?

- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS)-6 जारी किया है।



मुख्य बिन्दु:

- NFHS-6 का संचालन 2023-24 के दौरान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया गया था, जिसमें मुंबई स्थित अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान नोडल एजेंसी थी।
- 715 जिलों में फैले लगभग 6.79 लाख परिवारों को कवर करने वाला यह सर्वेक्षण जनसंख्या, स्वास्थ्य, पोषण और परिवार कल्याण संकेतकों पर साक्ष्य प्रदान करता है।
- यह जिला स्तर तक साक्ष्य-आधारित योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन का समर्थन करता है।

-:22:-

प्रमुख निष्कर्ष

- **मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल में सुधार:** 95.9% गर्भवती महिलाओं को प्रसवपूर्व देखभाल प्राप्त हुई।
- **संस्थागत प्रसव:** संस्थागत प्रसवों में 88.6% से वृद्धि होकर 90.6% हो गई है, जिससे भारत सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के करीब पहुँच गया है। कुशल स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा कराए गए प्रसवों में सुधार होकर 91.3% हो गया है।
- भारत में भी सीजेरियन सेक्शन से होने वाली प्रसवों की दर में तेजी से वृद्धि हुई है, जो 27.2% हो गई है। शहरी क्षेत्रों में सीजेरियन सेक्शन की दर 40% है। यह दर विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित 10-15% की आदर्श सीमा से कहीं अधिक है।
- **मातृ पोषण:** गर्भावस्था के दौरान 100 दिनों या उससे अधिक समय तक आयरन और फोलिक एसिड सप्लीमेंट का सेवन करने वाली माताओं की संख्या 54.9% हो गई, जबकि 180 दिनों या उससे अधिक समय तक सप्लीमेंट का सेवन करने वाली माताओं की संख्या 37.8% हो गई।
- **परिवार नियोजन:** भारत की कुल प्रजनन दर (TFR) 2.0 पर स्थिर है। गर्भनिरोधक उपयोग दर बढ़कर 69.1% हो गई है, जिसमें मां और बच्चे के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया गया है।
- **बाल टीकाकरण की सफलता :** टीकाकरण कार्ड के आधार पर 12-23 महीने की आयु के बच्चों में पूर्ण टीकाकरण कवरेज बढ़कर 87.1% हो गया।
- 95.6% बच्चों को अधिकांश टीके सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से लगाए गए।
- **बाल पोषण:** सर्वेक्षण अवधि के दौरान छह महीने से कम उम्र के 95.6% बच्चे स्तनपान कर रहे थे।
- पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों में बौनापन (उम्र के हिसाब से कम कद) में काफी कमी आई है, जो घटकर 29.3% हो गया है।

Daily Current Affairs

 Date : 01 June, 2026



- अत्यधिक कुपोषण (ऊँचाई के हिसाब से बहुत पतला होना) में 5.2% तक की तीव्र गिरावट दर्ज की गई, जबकि पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों में कम वजन की व्यापकता में भी 31.8% तक गिरावट दर्ज की गई।
- **स्वास्थ्य सुरक्षा का विस्तार:** घरेलू स्तर पर स्वास्थ्य बीमा/वित्तपोषण योजना का कवरेज 41.0% से बढ़कर 60.2% हो गया है।
- **महिला सशक्तिकरण और वित्तीय समावेशन:** इंटरनेट का उपयोग करने वाली महिलाओं की संख्या लगभग दोगुनी होकर 64.3% हो गई।
- जिन महिलाओं के पास बैंक या बचत खाता है जिसका वे स्वयं उपयोग करती हैं, उनकी संख्या बढ़कर 89.0% हो गई है, और जिन महिलाओं के पास मोबाइल फोन है, जिसका वे स्वयं उपयोग करती हैं, उनकी संख्या बढ़कर 63.6% हो गई है।
- 15-24 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं में मासिक धर्म की सुरक्षा के लिए स्वच्छतापूर्ण तरीकों के उपयोग में 79.2% की वृद्धि हुई है।

बेबेसिया संक्रमण

(स्रोत: THE HINDU)



चर्चा में क्यों?

- गुजरात में बेबेसिया संक्रमण के संदेह के चलते शेर के आठ शावकों की मौत हो गई है, जिससे एशियाई शेरों की आबादी के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएँ बढ़ गई हैं।



मुख्य बिन्दु:

- बेबेसिया एक परजीवी रोग है जो टिक के माध्यम से फैलता है और संक्रमित जानवरों में कमजोरी, बुखार, खांसी और नाक से स्राव का कारण बन सकता है।
- यह एक जूनोटिक बीमारी है, जिसका अर्थ है कि यह जानवरों से मनुष्यों में फैल सकती है।
- एटोवाक्वोन और एज़िथ्रोमाइसिन का संयोजन अधिकांश हल्के से मध्यम मामलों के इलाज के लिए किया जाता है।

एशियाई शेर (पैंथेरा लियो पर्सिका)

संरक्षण की स्थिति:

- आईयूसीएन रेड लिस्ट में स्थिति: संकटग्रस्त
- CITES: परिशिष्ट I
- वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972: अनुसूची I

-:25:-